बुनियादी आय असरदार है : एक प्रश्न

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक- गाए स्टैंडिंग (प्रोफेसनल रिसर्च एसोसिएट, एसओएएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन)

14 जनवरी, 2019

"भारत में तकनीकी क्षमता, वित्तीय संसाधन और सरल, पारदर्शी बुनियादी आय योजना की आवश्यकता है।"

वर्ष 2010-2013 में, मैं (लेखक) पश्चिमी दिल्ली और मध्य प्रदेश में तीन बुनियादी आय पायलट प्रोजेक्ट का प्रमुख डिजाइनर था, जिसमें 6,000 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को नकद, मासिक रूप से बिना शर्तों के बुनियादी आय के साथ भुगतान किया गया था। हांलाकि, यह भुगतान ज्यादा नहीं था, अर्थात् यह केवल निर्वाह का एक तिहाई था। लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया गया था, जहाँ पुरुषों और महिलाओं को समान मात्रा में और बच्चों को आधा माँ या सरोगेट माँ के भुगतान का आधा दिया गया। इस पायलट प्रोजेक्ट में स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA) और यूनिसेफ और UNDP की वित्तीय सहायता भी शामिल थी।

परिणाम कई अपेक्षाओं से अच्छा रहा, क्योंकि समुदाय में हर किसी को अपना व्यक्तिगत स्थानांतरण प्राप्त हुआ था। पोषण में सुधार, स्वच्छता में सुधार, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार, स्कूल में उपस्थिति और प्रदर्शन में सुधार, महिलाओं की स्थिति एवं स्वास्थ्य में सुधार, विकलांग और कमजोर समूहों की स्थिति दूसरों की तुलना में बेहतर हुई थी और काम की मात्रा और गुणवत्ता में भी सुधार हुआ।

हालांकि, आलोचकों का कहना था कि यह पैसे की बर्बादी है, लेकिन वे गलत साबित हुए। इसने सबसे पहले, मूल आय ने सामुदायिक भावना में सुधार किया और वे अनुकरणीय थे। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, वे दशकों से चले आ रहे सबूतों के बावजूद पैतृक नीतियों को बनाए रखना चाहते हैं जबकि यह व्यापक रूप से अक्षम, अप्रभावी, असमान हैं और भ्रष्टाचार को निमंत्रण देता हैं। आम लोगों को अपने विवेकाधीन परोपकार के प्रति आभार व्यक्त करने की इच्छा रखने की प्रवृत्ति ने समझदार आर्थिक सुधार को अवरुद्ध कर दिया है।

जैसा कि टिप्पणीकारों को पता है कि 2017 में सरकार द्वारा पेश की गई आर्थिक रिपोर्ट में एक अध्याय यह भी है कि कैसे पूरे भारत में एक मूल आय को सभी के लिए लाया जा सकता है। इसके मुख्य लेखक, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और प्रोफेसर प्रणब बर्धन जैसे अन्य लोगों ने इसके लिए भुगतान करने के तरीके प्रस्तावित किए हैं - मुख्य रूप से मौजूदा बेकार, विकृतिपूर्ण और ज्यादातर प्रतिगामी सब्सिडी वापस करके। इसे राजनीतिक विभेद का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए।

एक उन्नत विचार

बुनियादी आय पर अंतर्राष्ट्रीय बहस पिछले पांच वर्षों में काफी उन्नत हुई है। प्रति व्यक्ति आय के विभिन्न स्तरों के देशों में प्रयोग शुरू किए गए हैं, जिसमें कनाडा, फिनलैंड, केन्या, नामीबिया, नीदरलैंड, स्पेन और अमेरिका शामिल हैं और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, दक्षिण कोरिया जैसी अन्य जगहों पर इसे तैयार किया जा रहा है। अब बारी भारत की है। भारत को तकनीकि क्षमता, वित्तीय संसाधन और सब से ऊपर, जनता की ऊर्जा को मुक्त करने के लिए एक सरल, पारदर्शी योजना की आवश्यकता है, जो अभी आर्थिक असुरक्षा, अभाव और गिरावट के कारण समस्याग्रस्त है।

इससे पहले लेखक ने कहा था कि मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद, मूल आय के चरणबद्ध कार्यान्वयन की योजना एक गंभीर, लेकिन प्रबंधनीय चुनौती होगी। इसमें अपरिहार्य गलतियों के बारे में सद्भावना, अखंडता, ज्ञान और विनम्रता की आवश्यकता होगी। जैसा कि हमने पाया, अगर ठीक से योजना बनाई गई है, तो बहुत अधिक लागत के बिना, ग्रामीण या शहरी कम आय वाले समुदायों में भी एक व्यापक योजना शुरू करना संभव है। लेकिन शुरुआत में स्थानीय सहयोग और जागरूकता और प्रमुख स्थानीय संस्थानों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। यदि सरकार को आगे बढ़ना है, तो उसे स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित और तैयार किए जाने के बाद, इसे धीरे-धीरे कम आय से उच्च-आय वाले समुदायों तक ले जाना चाहिए।

यह सिफारिश की जाती रही है कि अधिकारियों को विशेष प्रकार के व्यक्तियों का चयन नहीं करना चाहिए और इसे केवल उनके के ही अधीन नहीं दे देना चाहिए। यह कहना गलत होगा कि इसे केवल महिलाओं, कम आय वाले किसानों या कमजोर सामाजिक समूहों तक जाना चाहिए। इसमें महंगी और भ्रष्ट प्रक्रियाएं शामिल होंगी और मनमाने तरीके से बाहर रखे गए लोगों में आक्रोश फैलने का जोखिम भी होगा, जिसकी आवश्यकता इनको भी समान रूप से होगी।

यदि पैसा केवल महिलाओं को दिया जाता है, तो पुरुष महिला से एक हिस्से की मांग करेंगे; जिसमें कुछ महिलाएं इसके लिए विरोध करेंगी और कुछ विरोध नहीं करेंगी; यह विभाजनकारी होगा। हमने पायलट प्रोजेक्ट में पाया कि यदि पुरुष और महिला सभी के पास एक समान राशि है, तो यह बेहतर और अधिक समान लिंग संबंधों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, स्थानीय अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव को सक्षम करने के अलावा, घरों और व्यापक समुदाय के भीतर समुदाय की एकता को बढ़ावा देता है।

कृषि ऋण माफी

यह विषमता कांग्रेस के कृषि ऋण माफी के वादे के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि यह नीति एक कठोर सामाजिक समूह पर बोझ को कम करेगी और ग्रामीण गरीबी को कम करेगी, लेकिन यह एक लोकलुभावन उपाय है। यह लोकप्रिय होगा, लेकिन संरचनाओं में बदलाव नहीं करेगा और यह एक खराब अर्थशास्त्र है। मान लीजिए कि सिद्धांत सामान्यीकृत थे। यदि एक प्रकार का ऋण गैर-चुकौती योग्य घोषित किया जा सकता है, तो अन्य क्यों नहीं? जब तक कोई यह नहीं दिखा सकता है कि एक ऋण प्रति व्यक्ति अवैध है या नहीं, तो यह घोषित करना खतरनाक साबित होगा कि एक प्रकार के ऋण को चुकाना पड़ेगा और दूसरे प्रकार के ऋण को किसी को नहीं चुकाना पड़ेगा।

दीर्घावधि में, वित्तीय संस्थानों में छोटे पैमाने पर किसानों को ऋण देने की संभावना कम होगी। यदि ऋण निष्पक्ष नियमों पर किए गए थे, तो बेहतर होगा कि देनदार उन्हें कम से कम भुगतान करें। इसलिए एक बुनियादी आय ग्रामीण त्रासदी को कम करने में एक अधिक न्यायसंगत और आर्थिक रूप से तर्कसंगत तरीका साबित होगा।

इससे सभी वर्ग लाभान्वित होंगे। यह विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए विशेष अतिरिक्त समर्थन प्रदान करेगा और साथ ही यह देशांतर में प्रगतिशील कल्याणकारी राज्य के लिए कोई खतरा भी साबित नहीं होगा। यह 21 वीं सदी की आय वितरण प्रणाली के लिए काफी सहयोगी साबित होगा। हालांकि, अब सवाल यह है कि क्या राजनेताओं द्वारा इसे लागू करने में दिलचस्पी दिखाई जाएगी या इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा?

GS World टीम...

यूनिवर्सल बेसिक इनकम

क्या है?

- 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' से तात्पर्य एक ऐसी 'न्यूनतम आधारभूत आय' से है, जो किसी देश की सरकार या उस देश की कोई सार्वजनिक संस्था, देश के नागरिकों या निवासियों को बिना किसी शर्तों के नियमित तौर पर आजीविका हेतु प्रदान करती है।

आवश्यकता क्यों?

- वस्तुत: सार्वभौमिक बुनियादी आय एक प्रकार का बेरोजगारी बीमा होती है, जो हर किसी को प्रदान नहीं किया जा सकता है। अत: इसे लागू करने के लिये कुछ विशेष पैमाने तय करने की आवश्यकता है।
- इसका मुख्य कारण यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक को बुनियादी आय प्रदान करने हेतु आवश्यक धन सरकार के पास नहीं होता है, अत: यही कारण है कि सरकार इसे सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।
- यहाँ यह स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है कि दीर्घकाल से विकसित देशों के द्वारा हमेशा यह इच्छा प्रकट की गई है कि भारत खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित प्रावधानों (राज्यों द्वारा खाद्यान्नों की खरीद एवं उनका सब्सिडीयुक्त वितरण) का विस्तार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करे। ताकि इससे एक सार्वभौमिक बुनियादी आय के निराकरण के लिये मार्ग खुल सकें।

चुनौतियाँ

- बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि सबके लिये बेसिक इनकम का बोझ कोई बहुत विकसित अर्थव्यवस्था ही उठा सकती है, जहाँ सरकार का खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 40 फीसदी से भी ज्यादा हो और टैक्स से होने वाली कमाई का आँकड़ा भी इसके आसपास ही हो। यदि हम भारत की बात करें तो टैक्स और जीडीपी का यह अनुपात 17 फीसदी से भी कम बैठता है, यानी हम तो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और आधारभूत ढाँचे के अलावा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, मुद्रा और बाहरी संबंधों से जुड़ी संप्रभु प्रक्रियाओं का बोझ ही बहुत मुश्किल से उठा पा रहे हैं।
- बेसिक इनकम की राह में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 'बेसिक आय' का स्तर क्या हो, यानी वह कौन-सी राशि होगी, जो व्यक्ति की अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके? मान लें कि हम गरीबी रेखा का पैमाना लेते हैं, जो कि औसतन चालीस रुपए रोजाना है (ग्रामीण क्षेत्रों में बत्तीस रुपए और शहरी क्षेत्रों में सैंतालीस रुपए), तो प्रत्येक व्यक्ति को लगभग चौदह हजार रुपए सालाना या बारह सौ रुपए प्रतिमाह की गारंटी देनी होगी।
- प्रथम दृष्टया यह राशि व्यवहारिक प्रतीत होती है, लेकिन यदि हम इस प्रकार देखें कि अपनी कुल जनसंख्या के पच्चीस फीसद को सालाना चौदह हजार रुपए और अन्य पच्चीस फीसद आबादी को सालाना सात हजार रुपए देने की जरूरत पड़ेगी और बाकी आबादी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं होगी, तो ऐसे में योजना की लागत आएगी प्रतिवर्ष 693,000 करोड़ रुपए।
- विदित हो कि यह राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार के भुगतान बजट के पैंतीस फीसद के बराबर है। जाहिर है, वर्तमान परिस्थितियों में यह आवंटन सरकार के लिये सम्भव नहीं है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

   1. यूनवर्सल बेसिक इनकम एक प्रकार की बेरोजगारी बीमा है जो सभी समूह के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
   2. यूनवर्सल बेसिक इनकम को सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2017 में लाया गया।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में चर्चा करते हुए बताइए, कि भारत में गरीबी उन्मूलन ये कहा तक सहायक होगा? (250 शब्द)

नोट : 12 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(c) होगा।

GS World
Committed To Excellence